



प्रधानमंत्री जन-धन योजना के दस वर्ष

प्रलम्ब के लिये:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, ओवरड्राफ्ट सुविधा, वित्तीय साक्षरता, जन धन दर्शक ऐप, माइक्रो इन्शोरेंस, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) एवं भारतीय बैंकिंग पर इसका प्रभाव, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) का दसवाँ वर्ष है। PMJDY को दस वर्ष पूर्व 28 अगस्त, 2014 को लॉन्च किया गया था।

- सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान PMJDY के तहत 3 करोड़ से अधिक खाते खोलना है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- खाता वसतिार:** मार्च, 2015 में PMJDY ने 147 मिलियन खाते खोले थे, जो मार्च, 2024 में 520 मिलियन खातों तक पहुँच गया है।
- जमा संग्रहण:** मार्च, 2015 में जमा संग्रहण 15,600 करोड़ रुपए था, जो मार्च, 2024 में बढ़कर 2.32 ट्रिलियन रुपए हो गया।
 - पछिले 10 वर्षों में जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धिदर से बढ़ा है।
 - मार्च, 2015 में औसत शेष राशि 1,065 रुपए से बढ़कर मार्च 2024 में 4,476 रुपए हो गई, जो पछिले दशक में लगभग चार गुना है।
- बैंकिंग अवसरचना का वसतिार:** जन धन दर्शक (JDD) ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किये गए हैं।
 - जुलाई, 2023 तक JDD ऐप पर कुल 6,01,000 गाँव मैप किये गए हैं। इनमें से कुल मैप किये गए गाँवों में से 5,99,468 (99.7%) गाँवों में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा, बैंकिंग कॉर्नर, या 5 कमी के दायरे में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की सुविधाएँ हैं।
 - जन धन दर्शक ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो नागरिकों को शाखाओं, ATM, बैंकिंग संवाददाता (BC), IPPB आदि जैसे बैंकिंग टचपॉइंट्स का पता लगाने में मदद करता है।
- ग्रामीण-शहरी समानता:** वित्त मंत्रालय के अनुसार, PMJDY ने कुल 53.13 करोड़ PMJDY खातों की उपलब्धि हासिल की, जिसमें से 55.6% (29.56 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएँ हैं और 66.6% (35.37 करोड़) जन धन खाते ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- डिजिटल भुगतान में वृद्धि:** UPI वित्तीय लेन-देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 920 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131.2 बिलियन हो गई है।
 - इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल (PoS) और ई-कॉमर्स पर RuPay कार्ड लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 670 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.26 बिलियन हो गई है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** PMJDY ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से लाभार्थियों को लगभग 361 बिलियन अमरीकी डॉलर सीधे हस्तांतरित किये।
 - कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत PMJDY खातों ने तीन महीने (अप्रैल, मई और जून 2020) के लिये 500 रुपए प्रतिमाह के एकमुश्त अनुग्रह भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 206.4 मिलियन महिला खाताधारक लाभान्वित हुईं।
- ओवरड्राफ्ट (OD) खाते:** मार्च, 2024 तक ऐसे PMJDY खाताधारकों के लिये 190 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के साथ कुल 1,17,701 ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते खोले गए हैं। इस सीमा का उपयोग 80.5% है।
 - इसने सबसे गरीब लोगों के लिये औपचारिक वित्तीय प्रणाली से ऋण तक पहुँच सुनिश्चित की है।
- कम शून्य शेष वाले खाते:** यद्यपि PMJDY के तहत शून्य शेष वाले खातों की अनुमति है और न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य नहीं है, फरि

भी केवल 8.4% खातों में शून्य शेष राशि है।

- **वशिव बैंक द्वारा प्रशंसा:** वशिव बैंक के अनुसार, भारत ने छह वर्षों में इतना कुछ हासिल कर लिया है जितना वह पाँच दशकों में नहीं कर पाता।
 - **जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति** ने वित्तीय समावेशन दर को वर्ष 2008 के 25% से बढ़ाकर 80% वयस्कों तक पहुँचा दिया है, यह प्रगति जिससे पूरा होने में 47 वर्षों का समय लगता, **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के कारण संभव हुई है।

PMJDY क्या है?

- PMJDY एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कफियाती तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे मूल बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुँच सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत जनि व्यक्तियों के पास कोई अन्य खाता नहीं है, वे किसी भी बैंक शाखा या बज़िनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट (बैंक मतिर) आउटलेट में मूल बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोल सकते हैं।
- **वशिषताएँ:**
 - कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं: PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
 - निःशुल्क डेबिट कार्ड: PMJDY खाताधारकों को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
 - दुर्घटना बीमा: 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर (वर्ष 2018 से खोले गए नए PMJDY खातों के लिये 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया) PMJDY खाताधारकों को जारी किये गए रुपे कार्ड के साथ उपलब्ध है।
 - OD सुविधा: पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा उपलब्ध है।
 - DBT लाभ: PMJDY खाते DBT, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के लिये पात्र हैं।
 - हालाँकि PMJDY खाते के साथ कोई अनिवार्य निःशुल्क चेक बुक सुविधा नहीं है। बैंक PMJDY खातों पर चेक बुक जारी कर सकते हैं, जिनकी कीमत हो भी सकती है और नहीं भी।

PMJDY से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **एक से अधिक खाते:** बड़े बीमा कवर, आकस्मिक मृत्यु लाभ कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा पाने के लालच में लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे विभिन्न पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न बैंकों में कई खाते खोल लेते हैं।
- **बैंकों पर आर्थिक बोझ:** बहुत अधिक संख्या में ऐसे खाते जनिमें लगातार कम शेष राशि रहती है, उनके प्रबंधन में बैंकों के लिये वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **धन शोधन:** ऐसी चिंताएँ हैं कि गरीबों के जन धन खातों का उपयोग काले धन के संचालकों द्वारा धन शोधन में किया जाता है।
 - **वमिदरीकरण** के बाद जनधन खातों का उपयोग धन शोधन के लिये किया गया।
- **ओवरड्राफ्ट सुविधा में कमी:** OD सुविधा प्रदान करना संबंधित बैंकों का वविकाधिकार है। कई बैंक OD सुविधा देने से मना कर देते हैं, जिससे उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।
- **अधिकार का दुरुपयोग:** कभी-कभी व्यवसाय संवाददाता (Business Correspondents- BC) अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन दयनीय बना देते हैं।
 - BC उन सेवाओं के लिये अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं जो निःशुल्क या न्यूनतम लागत वाली मानी जाती हैं, जैसे बैंक खाते खोलना, लेन-देन की प्रक्रिया करना या ऋण प्रदान करना।
- **बैंड लोन:** यह संभावना है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंकों के लिये बैंड लोन के रूप में समाप्त हो सकती है, क्योंकि इस योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैंक ऋण कैसे वसूल सकते हैं।
 - अतीत में अनेक ऋण माफ़ी योजनाओं के कारण लोग ऋण को मुफ्त में मलिन वाली वस्तु मानने लगे हैं।
- **वित्तीय एवं प्रोद्योगिकी नरिक्षरता:** बचत, उधार, नविश और व्यय के बारे में नरिणय लेने के लिये ग्रामीण लोगों में जागरूकता, ज्ञान तथा कौशल की कमी है।
 - वित्तीय सेवा क्षेत्र की दगिगज कंपनी वीजा द्वारा कयि गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 65% भारतीयों में वित्तीय साक्षरता का अभाव है।

आगे की राह

- **केंद्रीकृत सत्यापन प्रणाली:** बायोमेट्रिक और डिजिटल पहचान सत्यापन का उपयोग करके खातों के दोहराव को रोकने के लिये एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू करना।
 - व्यक्तियों को एक से अधिक खाते रखने के स्थान पर एक ही खाता रखने के लिये प्रोत्साहित करना, जैसे कि बढ़े हुए लाभ या कम शुल्क।
- **वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय रणनीति (NSFI):** वर्ष 2025-30 के लिये आगामी NSFI को लक्षित जनसंख्या के बीच सामाजिक सुरक्षा योजना की पहुँच और जागरूकता बढ़ाने हेतु PMJDY पर ज़ोर देना चाहिये।
- **सभी के लिये बीमा:** भारत को केवल खातों और शेष राशि पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
 - PMJDY खाताधारकों को सूक्ष्म बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
 - PMJDY खाताधारकों की माइक्रो-क्रेडिट और फ्लेक्सी-आवर्ती जमा जैसे माइक्रो नविश तक पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।
- **OD खातों की पहुँच में वृद्धि:** ओडी खातों की पहुँच में सुधार किया जाना चाहिये ताकि PMJDY वकिस के एक अच्छे चरण के लिये उत्प्रेरक बन सके और वकिसति भारत की दशा में योगदान दे सके।
- **नए फोकस क्षेत्र:** केंद्र का मानना है कि PMJDY ने वयस्क आबादी के अधिकांश हिस्से को शामिल कर लिया है। अब हमारा ध्यान संपूर्ण वयस्क

आबादी और वयस्कता प्राप्त करने वालों को भी शामिल करने पर है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: आलोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिये कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन में किस प्रकार मदद की है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न: भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में नमिनलखिति को ऋण देना शामिल है: (2013)

- (a) कृषि
- (b) सूक्ष्म और लघु उद्यम
- (c) कमजोर वर्ग
- (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

प्रश्न. 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' नमिनलखिति में से कसिके लयि प्रारंभ की गई है? (2015)

- (a) गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज-दर पर आवास-ऋण प्रदान करने के लयि।
- (b) पछिडे क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहति करने के लयि।
- (c) देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेशियल इंकलूजन) को प्रोत्साहति करने के लयि।
- (d) उपांतकि (मार्जनिलाइज़्ड) समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लयि।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लयि आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लयि तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2016)

प्रश्न .भारत की संभावति वृद्धिके कई कारकों में से बचत दर सबसेअधिक प्रभावी है। क्या आप सहमत हैं? वकिस क्षमता के लयि अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं? (2017)